



भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)

(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH. & FAX : (0512) 2332222

Mob. : 09415733686, 09335621629, 09235729390 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

REF: BPMS/ MoD/ Qtrs/ 186(8/1/R)

Dated: 14.06.2020

To,
The Secretary
Govt of India, Ministry of Defence
South Block, DHQ PO
New Delhi- 110011

Subject: Relaxation in allotment rules of Quarters- Extension of retention period of Qtrs in view of Novel Corona virus (Covid-19).

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2 माह से अधिक समय से पूरा देश लॉक-डाउन में रहा है। इस दौरान किसी भी तरह की आवागमन गतिविधि पूरी तरह से ठप्प रही। जिसकी वजह से विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारी, जिन्हें इस दौरान आवंटित सरकारी आवास छोड़ना था, वे उसे छोड़ नहीं सकें।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए संपदा निदेशालय द्वारा (Directorate of Estate, Ministry of Housing and Urban Affairs) अपने विभिन्न निर्देशों के माध्यम से ऐसे सभी कर्मचारियों जो इस दौरान या लॉक-डाउन लागू होने से पूर्व सरकारी आवास को छोड़ने के पात्र थे, उन्हें सामान्य लाइसेन्स शुल्क पर आवास में रहने की छूट प्रदान की गयी। संपदा निदेशालय द्वारा अपने दिनांक 01 जून 2020 के पत्र के माध्यम से यह छूट 30 जून 2020 तक सीमित कर दी गयी।

चूँकि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालयों के आवास सम्बन्धी अपने नियम हैं जैसे आयुध निर्माणी बोर्ड हेतु रक्षा आवासों का आवंटन (रक्षा सेवा में सिविलियनों के लिए आयुध कारखाना वास सुविधा) नियम, 2003 [SRO 149/2004] एवं डी0जी0क्यू0ए0 हेतु SRO 1E/1996 आदि एवं इन नियमों के अन्तर्गत संस्थानों के विभाग प्रमुख जैसे आयुध निर्माणियों के मामले में निर्माणियों के वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक व डी0जी0क्यू0ए0 के मामले में आवास समिति की अनुशंसा पर आवंटन अधिकारी आदि को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं कि वह नियमों में छूट सम्बन्धी विभिन्न मामलों में निर्णय ले।

चूँकि विभिन्न तरह की समस्याएँ अभी भी व्याप्त हैं, जिनका निकट महीनों में समाधान नहीं दिख रहा है। कई स्थानों में, जहाँ पर विभिन्न रक्षा संस्थान स्थित हैं जैसे मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता आदि, इस महामारी ने विकराल रूप

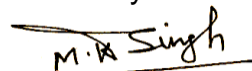
धारण कर लिया है। ऐसे समय में संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों को असहाय छोड़ देना नीतिगत नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को जो इस महामारी के दौरान या पूर्व में सरकारी आवास छोड़ने के पात्र हो गये हैं, उन्हें लॉक-डाउन लागू होने से लेकर अगले छः माह तक आवास में सामान्य लाइसेन्स शुल्क पर रहने की छूट प्रदान की जाय।

इस विषय पर अपने अधीनस्थ विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें कि वे अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को उपरोक्त छूट प्रदान करें।

Thanking you.

Sincerely Yours



(MUKESH SINGH)

General Secretary/ BPMS &
Member JCM II Level Council (MoD)